भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3938
25 **मार्च**, 2025 **को उत्तर के लिए**

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सीआरसीएफवी पहल

3938. **कैप्टन बृजेश चौटा**:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा ग्राम (सीआरसीएफवी) पहल के अंतर्गत गांवों के चयन के लिए क्या विशिष्ट मानदंड और पद्धति अपनाई गई है;
(ख) क्या इस पहल को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों और स्थानीय हितधारकों के साथ परामर्श हुआ था;
(ग) क्या समुद्री मात्स्यिकी और तटीय आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के किसी भी गांव को इस पहल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) इस बहिष्करण के कारणों का ब्यौरा क्या है और क्या चयन प्रक्रिया में समुद्री जैवविविधता, मत्स्यपालन पर निर्भर आजीविका और जलवायु संबंधी संवेदनशीलता जैसे कारकों पर विचार किया गया था;
(ङ) क्या सरकार की भविष्य में विशेषकर दक्षिण कन्नड़ से और अधिक गांवों को शामिल करने के लिए इस पहल का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे शामिल करने की समय सीमा क्या है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (च): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय समुदायों के विकास के महत्व को समझते हुए, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक परिवर्तनकारी पहल की है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के करीब स्थित मौजूदा 100 कोस्टल फिशरमन विल्लेजस को क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ फिशरमन विल्लेज बनाना है। तटरेखा के करीब स्थित मछुआरा गांवों को निम्नलिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करने के लिए पहचाना गया है:

1. तटीय मछुआरा गाँव जो उच्च ज्वार रेखा (हाई टाईड लाईन) के बहुत करीब स्थित है, जैसे कि; (i) 0-5 किमी, (ii) 0-10 किमी (उपर्युक्त (i) में कार्य पूर्णता के बाद), (iii) 0-20 किमी (उपर्युक्त (i) और(ii) में कार्य पूर्णता के बाद),
2. तटीय मछुआरा गाँव में मछुआरों की आबादी की अधिकता के आलोक में प्राथमिकता जैसे कि: (i) 100% मछुआरे, (ii) 90-100% मछुआरों की आबादी (उपर्युक्त (i) में कार्य पूर्णता के बाद), (iii) मछुआरों की आबादी 80 से 90% (उपर्युक्त(i) और (ii) में कार्य पूर्णता के बाद)
3. मछुआरा तटीय गाँव जिनकी इकाइयाँ निम्नलिखित संदर्भ में अधिक हैं; (i) मछुआरों की आबादी (ii) फिशिंग बोट्स की संख्या, (iii) फिश लैंडिंग और (iv) संबद्ध मात्स्यिकी आधारित आर्थिक गतिविधियाँ,
4. मछुआरों के तटीय गाँव, जहाँ भी संभव हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की नेशनल इन्नोवेशन इन क्लाइमेट रेसीलिएन्ट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) स्कीम के अंतर्गत लिए गए।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दो समितियों का गठन किया है, जिनके नाम हैं (i) क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेज की केंद्रीय समिति, (ii) क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विलेज की केंद्रीय स्थायी समिति। तटीय मछुआरा गांवों की पहचान संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उपर्युक्त व्यापक मानदंडों के अनुसार उचित परामर्श के बाद की जाती है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि मछुआरों के उन तटीय गांवों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें नेशनल इन्नोवेशन इन क्लाइमेट रेसीलिएन्ट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) स्कीम के अंतर्गत चुना गया है, और यदि एनआईसीआरए में विचार किए गए गाँव उपलब्ध नहीं है तो नजदीकी गांव को लिया जाता है जो एनआईसीआरए में विचारार्थ हैं, अत: पीएमएमएसवाई के अंतर्गत दक्षिण कन्नड़ जिले से क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विल्लेज के रूप में विकसित करने के लिए कोई गांव नहीं चुना गया ही । वर्तमान में क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेज कार्यक्रम के कवरेज को पहचाने गए 100 तटीय मछुआरा गांवों से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****